

असाधार ग

EXTRAORDINARY

भाग 🏻 — सण्ड ३--उपसण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 0 84

नर्द विरुषी, शुक्रवार, मार्च 9. 1973/फारगुम 18, 1894

No. 841

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 1973/PHALGUNA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्यादी जाती है जिससे कि यह श्रलग संकलन के कप में रखा जा सर्क।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, 9th March 1973

S.O. 131(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 772, dated the 11th March, 1966, read with the Order of the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 1085, dated the 10th March, 1971, the management of the industrial undertaking known as the Aurangabad Mills Limited, Aurangabad, had been taken over by the Authorised Controller referred to therein for a period of seven years up to and inclusive of the 10th March, 1973;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of the 10th March, 1975.

[No. F. 28013/31/73-TEX(G).]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

भौद्योगिक विकास मंत्रालय

धादेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1973

का॰ आ॰ 131 (म्).—यत भारत मरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का॰ आ॰ 772, विनांक 11 मार्च, 1966 द्वारा और भूतपूर्व विदेश ब्यापार मंत्रालय के आदेश कंश्रादेश संख्या का॰ आ॰ 1085, दिनांक 10 मार्च, 1971 के साथ पठित, औरंगाबाद मि॰स लिमिटेड, औरंगाबाद नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उसमें निदिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा सात वर्षों की श्रवधि के लिए 10 मार्च, 1973 तक] जिसमे यह तारीख भी शामिल है. ग्रहण कर लिया गया था।

श्रौर यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक-हित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त श्रौद्योगिक उपऋम का प्रवन्ध ग्रहण दो वर्ष की श्रवधि के लिए श्रौर बना रहना चाहिए ।

श्रतः, श्रब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) श्रिधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित श्रादेश का प्रभाव 10 मार्च, 1975 तक के लिये जिसमें यह नारीख भी शामिल है और बना रहेगा।

[सं॰ फा॰ 28013/31/73—टेक्स(जी)] दिनेश किशोर सक्सेना संयुक्त सचिव ।